फाइल संख्या-15011/36/2022-न्याय-(एयू)/ई-6889
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग

विषय : न्याय विभाग के संबंध में फरवरी, 2024- माह का मासिक सार ।

न्याय विभाग की फरवरी, 2024 माह की महत्वपूर्ण गतिविधियों निम्न है :

1. ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना :

क) **राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड :** राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड पर, दिनांक 02.02.2024 तक की स्थिति के अनुसार, 24.99 करोड़ से अधिक 'मामलों से संबंधित केस स्थिति सूचना और कंप्यूटरीकृत न्यायालयों से संबंधित 24.87 करोड़ से अधिक आदेशों/अधिनिर्णयों को देखा जा सकता है ।

ख) **ई-सेवा केन्द्र :** दिनांक 31-01-2024 तक 25 उच्च न्यायालयों के अधीन 886 ई सेवा केंद्रों को कार्यात्मक बनाया गया है ।

ग) **वर्चुअल कोर्ट:** 25 वर्चुअल कोर्टों द्वारा 4.43 करोड़ से अधिक मामलों को देखा गया है और दिनांक 31-01-2024 तक 48 लाख अधिक मामलों में, 506.56 करोड़ रुपए से अधिक का ऑनलाइन जुर्माना वसूल किया गया है ।

घ) **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग** : दिनांक 31-01-2024 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला और अधीनरख्य न्यायालयों ने 2,21,05,272 मामलों की सुनवाई की जबकि उच्च न्यायालयों ने 83,64,322 मामलों की सुनवाई की ।

• उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 03.02.2024 तक 6,52,534 मामलों की सुनवाई की ।

ङ. **ई-कोर्ट सर्विस मोबाइल ऐप :** ई-कोर्ट सर्विस मोवाइल ऐप डाउनलोड करने वालों की संख्या दिनांक 31-01-2024 तक 2.21 करोड़ पहुँच गई है ।

च) जस्टिस (Justis) ऐप: न्यायिक अधिकारियों के लिए इस मोबाइल ऐब को डाउनलोड करने की संख्या दिनांक 31-01-2024 तक कुल 19,537 हो गई है ।

छ) आई आई एम बैंगलोर में संचालित केंद्रीय परियोजना समन्वयकों, ई समिति के सदस्यों और न्यायिक अधिकारियों "के क्षमता सृजन कार्यक्रम :

“ई-कोर्ट के लिए डिजिटल ट्रांसफ़ोरमेशन और परियोजना प्रबंधन पर क्षमता सृजन कार्यक्रम के केंद्रीय परियोजना समन्वयकों, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के सदस्यों के लिए 2 बैंचों में और ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन में सन्निहित अन्य न्यायिक अधिकारियों के लिए आई आई एम बैंगलोर में दिनांक 5 फरवरी, 2024 से 9 फरवरी, 2024 तक और 12 फरवरी, 2024 से 16 फरवरी 2024 तक आयोजित किए गए थे ।

2. टेली लॉ : वंचितों तक पहुंच :

(क) माह के दौरान ग्राम स्तर के उद्यमियों/पैरा-लीगल स्वयं सेवकों (वीएलई-पीएलई), राज्य समन्वयकों और पैनल वकीलों द्वारा 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 58 जिलों में आयोजित 61 जागरूकता सत्रों/कैंपों में 1530 व्यक्तियों ने भाग लिया ।

(ख) माह के दौरान, 74,49,971 लाभार्थियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई जिसमें फरवरी, 2024 माह में दी गई सलाह के 4,73,998 लाभार्थी भी शामिल है"।

ग) माह के दौरान, 1530 ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) ने 32 प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया जो 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 58 जिलों में आयोजित किए गए थे।

घ) गोवा, असम, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य में उप थीम सबको न्याय- हर घर न्याय-अभियान के अंतर्गत इस माह में हमारा संविधान, हमारा सम्मान अभियान की राज्यस्तरीय कार्यशाला सह मेला आयोजित किए गए. जिनमें विभिन्न राज्य विभागों द्वारा नागरिक केंद्रित सेवा स्टॉल लगाए गए थे। इन क्षेत्रीय समारोहों' में 2600 से अधिक नागरिकों और संबंधित राज्य सरकार के प्रमुख प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित हुए ।

3. न्याय बंधु (प्रो-बोनो विधिक सेवा) कार्यक्रम :

माह के दौरान, 60 नए प्रो-बोनो वकील न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत हुए । कुल 10,839 (पुरुष-9075, महिला-1762, ट्रांसजेंडर-02) प्रो-बोनो वकील न्याय बंधु पोर्टल पर आ चुके है ।

4. विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम (LLLAP) :

क) बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान, पटना, बिहार ने 09 से 10 फरवरी, 2024 तक अररिया जिले के 95 न्याय मित्रों के साथ विधिक साध्तरता और विधिक जागरूकता कार्यशाला आयोजित की । बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान ने 11 से 12 फरवरी, 2024 तक किशनगंज जिले के 85 न्याय मित्रों के साथ दूसरी कार्यशाला आयोजित की । इन कार्यशालाओं के दौरान, विषय विशेषज्ञों ने दहेज निषेध, घरेलू हिंसा, बाल श्रम, बाल विवाह, साइबर अपराध, मानव तस्करी और नशा मुक्ति से संबद्ध कानूनों पर परस्पर संवादात्मक सत्र संचालित किए ।

(ख) नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU)) - बैंगलूरू, फर्नाटक ने 200 प्रतिभागियों के लिए 15 फरवरी, 2024 को 'महिला आधारित हिंसा : कानूनी संरक्षण" पर एक कार्यशाला आयोजित की। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ने 161 प्रतिभागियों के लिए 22-24 फरवरी, 2024 को "स्टार्टअप: विधिक, बौद्धिक और विनियामक अनुपालन" पर तीन दिवसीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आयोजित किया ।

ग) माह के दौरान, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD), पुणे, महाराष्ट्र ने धाराशिव जिले के 157 विधि दूतों के लिए 24 फरवरी, 2024 को और गढ़चिरोली जिले के 30 विधि दूतों के लिए 23-24-फरवरी, 2024 को विधिक साक्षारता एवं विधिक जागरूकला प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए ।

घ) राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली (NLU Delhi) ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों - बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा के 9 ग्रामों में 'महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकना और उसका समाधान' पर 9 'प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण' कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 265 ग्रामाणों में हिस्सा लिया ।

5- परियोजना मंजूरी समिति (PSC) : कार्रवाई अनुसंधान के लिए परियोजना मंजूरी समिति की 24वीं बैठक 10 फरवरी, 2024 को आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता सचिव (न्याय) द्वारा की गई । कार्रवाई अनुसंधान के तहत 7 (सात) नए प्रस्ताव परियोजना मंजूरी समिति (पीएससी) के समक्ष विचारार्थ और मंजूरी के लिए अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए गए थे ।

*****